लिया। 58 राउन्ड गोलियां चलाई गयी जिसके परिणामस्वरूप भीड़ में से 8 आदिवासियों की मृत्यु हो गई। तब भीड़ मृत पुलिस कार्मिकों की दो राइफलों को लेकर पीछे हट गई।

घायल पुलिस कार्मिकों को लगभग एक किलोमीटर दूर स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। भीड़ पुनः एकत्र हो गई और उसने घायल पुलिस कर्मियों को मारने के इरादे से अस्पताल पर आक्रमण किया। तब बल ने गोली चलाई जिससे 3 व्यक्ति घटनास्थल पर ही मारे गए।

परिणामस्वरूप एक घायल पुलिस कर्मी मर गया। इस प्रकार कुल दुर्घटनाएं इस प्रकार थी---4 पुलिस कार्मिक मारे गए, 17 पुलिस कार्मिक बुरी तरह घायल हुए और भीड़ में से 11 व्यक्ति पुलिस गोलीबारी से मारे गए।

राज्य सरकार ने मृत और घायल पुलिस कर्मियों द्वारा दिखाये गए उत्कृष्ट साहस और वीरता को देखते हुए उनके परिवारों को अनुग्रहपूर्वक अनुदान और पुरस्कार स्वीकृत किया है। राज्य सरकार ने आदिवासी जनसंख्या की वास्तविक कठिनाइयों को दूर करने के साथ-साथ वृक्षों को अवैध रूप से काटने में अंतर्ग्रस्त तत्वों से सख्ती से निपटने के लिए स्थानीय प्रशासन को भी सावधान कर दिया है।

(ख) प्रदर्शन झा खंड मुक्ति मोर्चा द्वारा आयोजित किये गये थे जिसने छोटा नागपुर क्षेत्र में वृक्षों के कटान सहित आंदोलन कार्यक्रम चलाया है। इसने हाल ही में गम्भीर रुख ले लिया है और चाईबासा जिले में बड़े पैमाने पर वृक्षों का काटा जाना सूचित किया गया। अवैध कटान को बेईमान ठेकेदारों और व्यापारियों द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा था। मल्यवान वन संपदा के बड़े पैमाने पर विनाश को रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन ने कुछ अवसरों पर गिरफ्तारियां की हैं।

चित्तौड़गढ़ को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करना

1307. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान का दक्षिणी भाग औद्योगिक रूप से पिछड़ा है;

(ख) क्या यह सच है कि अधिकांशत: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जातियों के लोग ही इस भाग में रहते हैं;

(ग) इस क्षेत्र के उन जिलों के नाम क्या क्या हैं जिन्हें औद्योमिक रूप से पिछड़ा घोषित किया गया है;

(घ) चित्तौड़गढ़ को औपचारिक रूप से औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित न करने के क्या कारण हैं जबकि यह औद्योगिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा है; और

(ङ) क्या चित्तौड़गढ़ को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित करने के बारे में कोई योजना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बरनजीत चानना) : (क) जी, हां।

(ख) 1971 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के 8 दक्षिणी जिलों में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या का प्रतिशत 11.85 है तथा जनजाति के लोगों की संख्या का प्रतिशत 30.81 है।

(ग) से (ङ). राजस्थान के 8 दक्षिणी जिलों अर्थात् सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बूंदी, कोटा तथा झालवाड़ में से सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा तथा झालवाड़ जिलों को अखिल भारतीय ऋणदायी संस्थानों

से रियायती दर पर वित्त की सुविधाएं मिली हुई है । इसके अलावा, इस क्षेत्र के उदयपुर जिले में केन्द्रीय निवेश राज-सहायता दी जाती है ।

राष्ट्रीय विकास परिषद की मुख्य मंत्रियों की समिति में लिये गये निर्णय के अनुसरण में योजना आयोग द्वारा राज्य सरकारो के परामर्श से औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए जिलों/क्षेत्रों का पता लगाया गया था । इस प्रयोजन के लिये लागू मानदण्डो के अनुसार चित्तौड़गढ़ जिले को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ घोषित नही किया गया था । पिछडे क्षेत्रो के समस्त प्रश्न को देखते तथा समस्या के प्रभावी रूप से निपटाये जाने हेतु प्रभावी सुझाव देने के लिये योजना आयोग के भूतपूर्व सदस्य श्री बी० शिवरामन की अध्यक्षता मे एक राष्ट्रीय समिति की स्थापना की गई है । समिति द्वारा सिफारिशें पेश किये जाने तथा सरकार द्वारा उन पर विचार कर लिये जाने के बाद ही आद्यो-गिक दृष्टि से पिछड़े हुए जिलो/क्षेत्रों की वर्तमान सूची में कोई परिवर्तन किया जा सकेगा ।

Zonal Council Meeting held in Trivandrum

1308. SHRI A A. RAHIM: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the concrete steps taken to implement the recommendations/conclusions arrived at the Zonal Council meeting held in Trivandrum in September last;

(b) whether Kerala Government has stressed for giving more assistance for developing tribal/plantation areas in Kerala; and

(c) if so, the action taken thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) Implementation of the recommendations made by the Southern Zonal Council in its last meeting will be taken up as soon as the proceedings of the meeting, which have been sent for comments of the member-States, are issued formally.

(b) No, Sir.

(c) Dos not arise.

गुजरात को सीमेंट की सप्लाई

1309. **श्री मोती भाई आर० चौधरी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य को अप्रैल, 1980 से सितम्बर, 1980 के बीच, उसकी माँग की तुलना में कितनी सीमेंट आवटित की गई और अक्तूबर से दिसम्बर के लिए कितनी;

(ख) उक्त मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ग) देश के अन्य राज्यों को की गई सप्लाई की तुलना मे गुजरात राज्य को कितनी सीमेट का आवंटन किया गया;

(घ) इस तथ्य को देखते हुए कि सीमेंट का उत्पादन देश की आवश्यकता को पूरा नही कर पा रहा है विदेशो से सीमेट का आयात न करने के क्या कारण है; और

(ङ) वर्ष 1978-79, 1979-80 तथा 1980-81 के दौरान विदेशों से कितनी सीमेंट का आयात किया गया, और उपरोक्त अवधि के दौरान देश का वार्षिक उत्पादन तथा मांग क्या रही ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना): (क) अप्रैल से दिसम्बर 1980 तक की तीन तिमाहियों में गुजरात राज्य